प्रेस विज्ञप्ति

12 अक्तूबर 2021

माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह ने श्री आलोक कुमार, सचिव (विद्युत), श्री आर.एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी तथा विद्युत मंत्रालय और पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिती में पीएफसी को भारत सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्रदान किए जाने पर बधाई दी।

सरकार द्वारा पीएफसी को "महारत्न" का दर्जा प्रदत्त

12 अक्तूबर 2021, नई दिल्ली: भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्वाधीन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) को प्रतिष्ठित 'महारत्न' का दर्जा प्रदान किया, इस प्रकार पीएफसी को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की। वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा आज इस आशय का आदेश जारी किया गया। 1986 में निगमित, पीएफसी आज सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, जो विशेष रूप से विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन विद्युत क्षेत्र को समर्पित है।

पीएफसी को 'महारत्न' दर्जा प्राप्त होने से वित्तीय निर्णय लेने के दौरान पीएफसी बोर्ड के पास संवर्धित शक्तियां होंगी। एक 'महारत्न' सीपीएसई का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक कंपनियों के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है तथा भारत और विदेशों में विलय एवं अधिग्रहण कर सकता है, जो संबंधित सीपीएसई के नेट वर्थ के 15% की सीमा के अध्यधीन है, एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए तक सीमित है। बोर्ड द्वारा कार्मिकों और मानव संसाधन प्रबंधन तथा प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी किए जा सकते हैं। वे प्रौद्योगिकी संयुक्त उद्यम या दूसरों के बीच अन्य कार्यनीतिक एलाएंस में भी प्रवेश कर सकते हैं।

माननीय केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर.के. सिंह ने पीएफसी को बधाई दी और टिप्पणी की कि महारत्न का दर्जा प्रदान करना, भारतीय विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास में पीएफसी की कार्यनीतिक भूमिका पर भारत सरकार के विश्वास और इसके उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के समर्थन का प्रतिबिंब है। यह नई मान्यता पीएफसी को विद्युत क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धी वित्तपोषण ऑफर करने में सक्षम बनाएगी, जो किफायती और विश्वसनीय '24X7 सभी के लिए विद्युत' उपलब्ध कराने में समर्थ बनाएगी। महारत्न की स्थिति के साथ आगामी संवर्धित शक्तियां, पीएफसी को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंतर्गत वित्तपोषण के सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने, वर्ष 2030 तक 40% हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ नई संशोधित वितरण क्षेत्र योजना की प्रभावी मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन में सहायक होगी।

श्री आर.एस. ढिल्लों, सीएमडी, पीएफसी ने कहा कि पीएफसी ने पिछले 3 वर्ष के दौरान असाधारण वित्तीय कार्य-निष्पादन के आधार पर महारत्न का दर्जा प्राप्त किया है। कोविड के बावजूद, पीएफसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान विद्युत क्षेत्र को क्रमशः 1.66 लाख करोड़ रुपए और 88,300 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे अधिक वार्षिक स्वीकृतियां और संवितरण की तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8,444 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक लाभ अर्जित किया। विद्युत क्षेत्र में लिक्विडिटी संकट को टालने के लिए लिक्विडिटी इंफ्यूजन योजना ('आत्मनिर्भर भारत योजना') के अंतर्गत डिस्कॉमों को वित्तपोषण करके पीएफसी ने कोविड के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महारत्न की संवर्धित शक्तियों के साथ, पीएफसी आगे चलकर अपने व्यवसाय के विकास में और तेजी लाने के लिए अपने कार्यों में विविधता लाएगा और विद्युत क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का लाभ उठाएगा। हम इस महान उपलब्धि को संभव बनाने में निगम के कार्मिकों और पूर्व प्रबंधन के उनके अथक समर्थन, योगदान और समर्पण के लिए बहुत आभारी हैं और विद्युत मंत्रालय के प्रति हमारी हार्दिक कृतज्ञता है जिनके समर्थन के बिना यह दर्जा/मान्यता संभव नहीं होती।

ह/-
(एस.एस. राव)
मुख्य महाप्रबंधक (पीआर)